

महिलाएं बनाएंगी उत्पाद, मार्केटिंग करके बेचेगी सरकार

जितेंद्र उपाध्याय • लखनऊ

आलमबाग की तृप्ता शर्मा स्वयं सहायता समूह बनाकर सब्जी मसाले के साथ ही जैम और जेली बनाती हैं। उनके समूह के साथ 300 महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन उनके उत्पादों की मार्केटिंग न होने से उनका उत्पाद नहीं बिक पाता। इस कारण समूह की महिलाओं को अपेक्षित लाभ नहीं हो पा रहा। अकेली तृप्ता शर्मा ही नहीं चिनहट की विभा ने ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह बनाया और पापड़, दाल, सत्तू, बेसन और आलू के चिप्स बनाने लगीं। 150 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ दिया, लेकिन मार्केटिंग का अनुभव न होने से उनका उत्पाद नहीं बिक रहा और अब वह दूसरा काम करने की तैयारी कर रही हैं।

ऐसे ही समूह बनाकर खाद्य उत्पाद बनाने वाली स्वयं सहायता

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग करेगा मार्केटिंग, विभाग मुख्यालय परिसर में बनेगा प्रदेश का पहला शोरूम



सप्रू मार्ग स्थित क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र • जागरण

समूह की महिलाओं को राहत देने की पहल उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग करने जा रहा है। सप्रू मार्ग स्थित विभाग के मुख्यालय के सामने शोरूम खुलेगा जिसमें महिला समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बेचा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अपनी तरह का यह पहला शोरूम होगा। इसकी सफलता के

बाद मंडल स्तर और फिर जिले स्तर पर विभागीय कार्यालयों के परिसर में शोरूम खोले जाएंगे।

खाद्य पदार्थों का होगा प्रमाणीकरण: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र (आरएफआरएसी) द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही गुणवत्ता युक्त

समूहों को मिलेगा 90 प्रतिशत लाभ

क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र के निदेशक डा. एसके चौहान ने बताया कि गुणवत्तायुक्त उत्पादों की बिक्री भले ही विभाग करेगा, लेकिन बिक्री के लाभ का 90 प्रतिशत हिस्सा उत्पाद बनाने वाले समूहों को मिलेगा। गुणवत्ता प्रमाणीकरण होने के साथ उत्पाद में कोई कमी नहीं रहेगी। ग्राहकों को प्रमाणीकृत उत्पाद मिलेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक लाभ होगा, क्योंकि मार्केटिंग के अभाव में जो उत्पाद नहीं बिक रहे थे, उनकी मांग बढ़ जाएगी।



डा. एसके चौहान • जागरण

खाद्य पदार्थों को शोरूम में रखा जाएगा। खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण के लिए कोई भी केंद्र में नमूना जमा कर सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित फीस के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसी अन्य केंद्र का प्रमाणीकरण स्वीकार नहीं होगा।

एक लाख महिलाओं को मिलेगा अवसर: राजधानी में 9,500 के

समूहों में एक लाख महिलाएं उत्पाद बनाती हैं। आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक अंबेश ने बताया कि मार्केटिंग का अवसर मिलने से करीब ढाई हजार समूहों को सीधे फायदा होगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पहल सराहनीय है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी।